युवाओं को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देकर रोजगारपरक बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा

प्रदेश में निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए उठाए प्रभावी कदम : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम प्रदेश की आधारभूत संरचना, शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए ठोस और दीर्घकालिक बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि में एआई के उपयोग से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी, युवा अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगारपरक बनेंगे तथा निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण से प्रदेश में उद्योग के परिदृश्य में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव आएगा।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से बढ़ेगी कृषि उत्पादकता : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को कृषिगत सुधार, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने तथा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में बैठक ली।

भजनलाल शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर कृषिगत सुधार, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने तथा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि खेती में एआई को बढ़ावा देने के लिए हमने इस वर्ष के बजट में 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर' की स्थापना की घोषणा की है। इसके माध्यम से आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए, जिससे कृषि में गुणात्मक वृद्धि हो सके तथा युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू करना, सिंगल विण्डो प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन जैसे निर्णयों से प्रदेश में निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार किया गया है।

इसी क्रम में प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि बजट वर्ष में 2025-26 में डीएमआईसी (दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर) से लिंक करते हुए लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। जो राज्य की लॉजिस्टिक्स क्षमता को नई ऊंचाइयां देगा।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को 'फ्यूचर रेडी-इंडस्ट्री रेडी' बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को विश्व स्तरीय रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

इस दौरान राज्य में कृषि के क्षेत्र में एआई आधारित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित करने, शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक स्किल डवलपमेंट सेंटर तथा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के संबंध में प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

देश के प्रतिष्ठित तीन विश्वविद्यालयों से एकसाथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर

पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि अनुसंधान संस्थान एवं देश के तीन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा, चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, कौशल विकास, ज्ञान परम्परा में सहयोग एमओयू साइन किया गया।

जयपुर। पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि अनुसंधान संस्थान एवं देश के तीन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा, चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परम्परा एवं अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग एमओयू साइन किया गया। इस अवसर पर प्रो. इंद्र प्रसाद त्रिपाठी, कुलगुरु, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, डॉ. संजय तिवारी, कुलगुरु, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छत्तीसगढ़ एवं प्रो. भरत मिश्रा, कुलगुरु, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्य प्रदेश की उपस्थिति रही। सभी विद्वतजनों ने पतंजलि में हो रहे राष्ट्र निर्माण के कार्यो की प्रशंसा की। इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि द्वारा किए जा रहे इतिहास लेखन, वनस्पति शास्त्र लेखन, निदान ग्रन्थ, विश्व भेषज संहिता सहित अन्य शास्त्रों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि ऋषि क्रांति, योग क्रांति तथा शिक्षा क्रांति का यह सफ़र देश के लाखो लोगो को इसी प्रकार लाभान्वित करता रहेगा ऐसा हमे पूर्ण विश्वास है।

मुझे बदनाम करने से तुम्हारा काम बनता है तो चलो एक अहसान और सही: शेखावत

- अशोक गहलोत ने अपने पुत्र का राजनीतिक करियर बनाने के लिए मेरा नाम संजीवनी सोसाइटी प्रकरण में घसीटा, परंतु बुरी तरह असफल रहे : गजेन्द्र सिंह

जयपुर/जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत अपने पुत्र का राजनीतिक करियर बनाने के लिए संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी प्रकरण में मेरा नाम घसीटकर मुझे कलंकित करने के प्रयास में बुरी तरह असफल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने भी मुझे दोषमुक्त माना है। गहलोत स्वयं भली-भांति जानते थे कि मैं निर्दोष हूं। मेरा एकमात्र 'दोष' यह है कि मेरे परिश्रम और जोधपुरवासियों के मुझसे अपार स्नेह से न केवल उनके पुत्र, बल्कि स्वयं उनकी राजनीति पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है।

अशोक गहलोत के बयानों पर शेखावत ने कहा, मुझे बदनाम करने से तुम्हारा काम बनता है, तो चलो एक अहसान और सही। उन्होंने कहा कि मैं अशोक गहलोत से आग्रह करता हूं कि वे संजीवनी प्रकरण के पीड़ितों की वेदना का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ और पुत्र की देवतुल्य जनता द्वारा रचित पराजय की खीझ निकालने के लिए न करें। इसके बजाय यदि वे सरकार का मुखिया रहते हुए मुझे फंसाने के बजाय ईमानदारी से पीड़ितों को राहत पहुंचाने का प्रयास करते तो पीड़ितों का कुछ भला अवश्य हो सकता था।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत पर तंज कसा कि भाजपा की प्रचंड विजय के चलते अपने ही दल में अप्रासंगिक हो जाने के कारण यदि मेरे नाम की माला जलाने से आपका अपनी पार्टी में कुछ भला हो जाए तो इसे भी मैं अपना उन पर एक और अहसान ही मानूंगा।

197 ग्राम ड्रग्स व तस्कर पकड़ा

जयपुर/प्रतापगढ़ /कोटा। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) जयपुर सेल के अधिकारियों ने प्रतापगढ़ बस स्टैंड, प्रतापगढ़ (राजस्थान) में एक व्यक्ति से 197 ग्राम अवैध एमडी (मेफैड्रोन) बरामद उसे गिरफ्तार किया। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुन्देल ने बताया कि (सीबीएन) को एक विशेष सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्रतापगढ़ बस स्टैंड से मंदसौर की ओर अवैध एमडी (मेफैड्रोन) ले जाएगा। इस पर कार्यवाही करने के लिए सीबीएन जयपुर सेल के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और और रवाना किया गया। टीम ने इस मार्ग पर कड़ी निगरानी रख कर उस व्यक्ति की पहचान कर प्रतापगढ़ बस स्टैंड पर उसे रोककर उसके पास से 197 ग्राम अवैध एमडी (मेफैड्रोन) बरामद की।

विदेश यात्रा और विवाह की 50वी वर्षगांठ पर देवनानी का अभिनंदन

विधायकों और विधानसभा अधिकारियों ने 50 किलो फूलों की माला पहनाकर दी शुभकामनाएं

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को फ्रांस और जर्मनी की सफल अध्ययन यात्रा और देवनानी एवं उनकी धर्मपत्नी इंद्रा देवनानी के विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर विधायकों और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 50 किलोग्राम फूलों की माला पहनाकर बधाई एवं शुभ कामनाएं दी। शुक्रवार को दिन भर विधानसभा और राजकीय निवास पर देवनानी से मिलने वालों का तांता लगा रहा।विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रा देवनानी से लगातार परिवार एवं सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरणा, सहयोग एवं संबल मिल रहा है।

विकास चौधरी, मनीष यादव, नरेंद्र बुडानिया, ताराचंद जैन, रेवतराम राम, विश्वनाथ, दीपचंद खेरिया, जीवतराम, पूसाराम, देवीसिंह शेखावत, उदयलाल डांगी, कैलाशचंद मीणा, चुन्नीलाल, सुभाष मील, धर्मपाल, ललित यादव, श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी, हंसराज मीणा, शोभा चौहान सहित अनेक विधायको ने देवनानी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सार्वजनिक जीवन की उत्कृष्ट सेवाओं तथा वैवाहिक जीवन के लिए मंगल कामनाएं दी। इस मौके पर विधायक और विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देवनानी का अभिनन्दन किया और उनके नैतिक मूल्यों, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा व दांपत्य जीवन में समर्पण को प्रेरणा स्वरूप स्मरण किया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी देवनानी को बधाई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली और प्रदेश के कई मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण अन्य जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को फ्रांस और जर्मनी की सफल अध्ययन यात्रा और उनके विवाह की 50 वीं वर्षगांठ के लिए अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है। सहकारिता मंत्री गोतम दत्त और प्रतिपक्ष के नेता जूली ने विधान सभा पहुँचकर देवनानी को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी।

'अपीलीय अधिकारियों को न्यायिक अकादमी में ट्रेनिंग दिलाना सुनिश्चित करें मुख्य सचिव'

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल सचिव की ओर से अपीलीय अधिकारी के तौर पर सुनवाई के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर असंतुष्ठता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि खेल सचिव को अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है, जबकि वह स्वयं अपील का निर्णय करते समय अपनाई गई प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे।

इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि अपीलीय अधिकारी को किसी भी अपील पर निर्णय लेने से पहले कम से कम 5 से 7 दिन के लिए राजस्थान न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसके साथ ही यह उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होता है, जिन्हें किसी भी कानून के तहत किसी भी अपील पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। जिससे अपील के निर्णय के दौरान न्याय में चूक ना हो। यह कदम इसकी जरूरी है, क्योंकि जमीनी स्तर पर अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के पास आम आदमी को न्याय देने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन अगर वे गलती करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछना बहुत मुश्किल होता है।

जस्टिस अशोक जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मामले में अपीलीय अधिकारी का गत 28 अक्टूबर के आदेश को निरस्त करते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देकर तीन माह में नए सिरे से निर्णय करने के लिए मामला अपीलीय अधिकारी के पास भेजा है। वहीं अदालत ने अपीलीय अधिकारियों को किसी भी अपील पर निर्णय लेने से पहले न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करने के लिए आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भेजी है।

याचिका में अधिवक्ता तनय जैन ने याचिकाकर्ता ने स्वयं को टीटी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने का दावा करते हुए संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की 23 फरवरी, 2024 की जांच रिपोर्ट को खारिज करने के संबंध में अपीलीय अधिकारी के तौर पर काम कर रहे खेल सचिव के समक्ष अपील दायर की थी। अपीलीय अधिकारी ने बिना कारण बताए और याचिकाकर्ता को सुने बिना अपील को खारिज कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि अपीलीय अधिकारी ने विधि के प्रावधानों की पालना किए बिना केवल मशीनी अंदाज में आदेश पारित किया है। ऐसे में अपीलीय अधिकारी के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपीलीय अधिकारियों को न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में मुख्य सचिव को दिशा-निर्देश दिए हैं।

अर्द्ध न्यायिक अधिकारी कंप्यूटराइज्ड प्रोफार्मा निर्मित आदेश जारी नहीं कर सकते : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने ने जीएसटी से जुड़े मामले में कहा है कि अर्द्ध न्यायिक अधिकारी कंप्यूटराइज्ड प्रोफार्मा में निर्मित आदेश जारी नहीं कर सकते और ना ही यह आदेश की श्रेणी में आते हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह निर्देश विष्णु इलेक्ट्रिकल्स की याचिका पर दिया। खंडपीठ ने अपीलेट अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह दोनों पक्षों को सुनकर मामले का निस्तारण करे।

मामले से जुड़े अधिवक्ता डीपी शर्मा ने बताया कि धारा 169 के तहत जीएसटी अफसरों का दायित्व है कि वह आदेश की सूचना संबंधित व्यक्ति को दे। आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना सूचित करने की श्रेणी में नहीं आता है।

वहीं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी सूचना काल्पनिक मानी जाएगी।

दूसरी ओर अपीलेट अथॉरिटी ने कंप्यूटराइज्ड प्रोफार्मा में ही आदेश दिया है और प्रार्थी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया है। ऐसे में अपीलेट अथॉरिटी का आदेश निरस्त कर मामले में विधिक प्रावधानों पर नए सिरे से आदेश दिया जाए।

जे.ई.सी.सी. की तर्ज पर जयपुर के विद्याधर नगर में 6318 वर्गमीटर जमीन पर बनेगा कन्वेंशन सेंटर

सांगानेर में 2782 वर्गमीटर जमीन पर विकसित होगी जयपुर की सबसे बड़ी पार्किंग

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 212वीं बैठक जेडीए के मंथन सभागार में जेडीए आयुक्त आनन्दी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न जनहितैषी और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि/भूखंड आवंटन के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।

- नारायण विहार पुलिस थाने के लिए निजी खातेदारी की नारायण सागर विस्तार योजना में 1469 वर्गगज जमीन आवंटित

ग्राम रागपुरा रूपा (तहसील सांगानेर) में 2782 वर्ग मीटर भूमि को मास्टर प्लान में दर्शित स्पेशल एरिया के तहत पार्किंग के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय जयपुर शहर में बढ़ती पार्किंग की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण साबित होगा।

जेईसीसी की तर्ज पर एम.आई.सी.ई. सेंटर (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन) के निर्माण के लिए विद्याधर नगर योजना के सेक्टर-7 में 6318 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन को मंजूरी दी गई।

यह केंद्र जयपुर को एक प्रमुख व्यापार और पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।

निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण सागर विस्तार में सुविधा क्षेत्र की 1669.22 वर्गगज भूमि प्रस्तावित पुलिस थाना नारायण विहार के प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के लिए आवंटन करने का फैसला लिया।

इसी तरह निजी खातेदारी की योजना पर्ल रिंगेलिया के सुविधा क्षेत्र के भूखंड संख्या एफ-1 क्षेत्रफल 3300 वर्ग गज (2759.13 वर्ग मीटर) भूमि का स्कूल निर्माण के लिए आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया, जो शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करेगा।

निजी खातेदारी की योजना पर्ल रिंगेलिया के सुविधा क्षेत्र के भूखंड संख्या एफ-2 क्षेत्रफल 3800 वर्ग गज (3177.18 वर्ग मीटर) का हॉस्पिटल निर्माण के लिए आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता मिले।

जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 212वीं बैठक जेडीए के मंथन सभागार में जेडीए आयुक्त आनन्दी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

इसी तरह राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय प्रताप नगर, सांगानेर के सामने की तरफ मरीजों के परिजनो के लिए धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

ग्रेटर नगर निगम को बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम लांगडियावास में 4 हैक्टेयर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई, ताकि जयपुर शहर में बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन की हालात सुधारी जा सके।

इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण की लालचंदपुरा आवासीय योजना के भूखंड संख्या बी-190, बी-192, बी-194, बी-196, बी-198, बी-199, बी-201, बी-202, बी-214 कुल 9 भूखंड जो खसरा सीमा से प्रभावित हो रहे थे, उनके स्थान पर योजना के रिक्त भूखंडों में लॉटरी से आवंटन करने का निर्णय भी लिया। जेडीए की हीरालाल शास्त्री नगर योजना में सृजित भूखंड संख्या डी-1 से डी-16 का मौके पर 9 मीटर का पहुंच मार्ग निजी खातेदारी की भूमि से प्रभावित होने के कारण, आवंटित भूखंड संख्या डी-3, डी-4, डी-5, डी-6, डी-8, डी-9, डी-12 व डी-16 के स्थान पर विनिमय द्वारा समान क्षेत्रफल के अन्य भूखंड आमजन सूचना प्रकाशन के उपरांत लॉटरी से नियमानुसार आवंटन करने का फैसला लिया।

राजधानी जयपुर में शुक्रवार दोपहर को झमाझम बारिश हुई तो देखते ही देखते सड़कों पर पानी भर गया। जयपुर-सीकर मुख्य मार्ग पर ड्रेनेज कार्य अधरझूल में पड़ा होने के कारण यहां सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर बहता रहा। इस गंदगी की बदबू के कारण यहां से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। फोटो-राष्ट्रदूत

बजट घोषणा के मुताबिक तीन सैटेलाइट हॉस्पिटल्स को मंजूरी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा बजट वर्ष 2025-26 के दौरान की गई स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी घोषणा के तहत जयपुर जिले के मुरलीपुरा, प्रतापनगर जयपुर और कांकरोली-राजसमंद में 50-50 शैय्याओं वाले तीन नए सेटेलाइट चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे।

- जयपुर में मुरलीपुरा और प्रतापनगर तथा कांकरोली राजसमंद में 50-50 बैड के अस्पताल खुलेंगे

इन अस्पतालों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुल 101 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, सफाईकर्मी आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 4 पदों को समाप्त कर तथा 3 पदों को मशीन विद मैन सेवा के माध्यम से संचालित किया जाएगा।इन अस्पतालों में मरीजों को शीघ्र, सुलभ और सशक्त उपचार उपलब्ध कराने हेतु अत्याधुनिक तकनीक व स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, सफाईकर्मियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें प्रत्येक अस्पताल में 4 कर्मियों सहित कुल 12 सफाईकर्मी नियोजित होंगे।राज्य सरकार का यह निर्णय ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय प्रयास है।